



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

No. 85]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

(जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना)

नई दिल्ली, 20 मार्च 2018

विषय : बंगलादेश से जूट के बोरो के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कथित परिवर्चना से संबंधित परिवर्चना रोधी जांच की शुरूआत

सं. 7/3/2018-डीजीएडी—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है), ने एक पाटनरोधी जॉच में 20 अक्टूबर, 2016 की अपनी अंतिम जॉच परिणाम अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी द्वारा बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “जूट उत्पाद” अर्थात – (जूट यार्न/ट्विन (मल्टिपल फोल्डेड/केबल्ड और सिंगल), हेसियन फेब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 5 जनवरी, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2017- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क द्वारा आगे यथा संशोधित द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

और यतः, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) ने जूट के बोरो (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) भी कहा गया है) के घरेलू उत्पादकों की ओर से अधिनियम और 'नियमावली' के अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विचाराधीन उत्पाद (जो जूट उत्पादों का एक उत्पाद प्रकार है, संबद्ध वस्तु जिस पर मूल जाँच की गई थी) का जूट सैकिंग कपड़े (जिसे आगे जाँच के अधीन उत्पाद (पीयूआई) जो केवल बंगलादेश (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद का एक गैर-तैयार और उपांत्य रूप है, के आयातों द्वारा धोखे से आयात किया जा रहा है।

और यतः प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश द्वारा पीयूसी पर लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्चना के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये जाने के बाद एतद्वारा उक्त नियमावली के नियम 26(1) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की कथित परिवर्चना की जाँच की शुरुआत की जाती है ताकि कथित परिवर्चना की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और परिवर्चित उत्पाद के लिए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने की जरूरत की जाँच की जा सके।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'जूट सैकिंग बैग्स' हैं। जूट सैकिंग बैग्स को सीमाशुल्क शीर्ष 6305 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। जूट सैकिंग बैग्स' दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणामों में यथा अभिज्ञात विचाराधीन उत्पाद का एक प्रकार है।

ख. जाँच के अधीन उत्पाद

2. जाँच के अधीन उत्पाद जूट सैकिंग क्लार्थ है जिस पर पाटनरोधी शुल्क की परिवर्चना का आरोप है। परिवर्चित उत्पाद जूट सैकिंग बैग्स' के प्रयोग में आता है और जाँच के अधीन उत्पाद का कोई अन्य मुख्य प्रयोग नहीं है।

3. जाँच के अधीन उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 5310 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. मौजूदा उपाय

4. वर्तमान में लागू पाटनरोधी उपाय, जिन्हें कथित रूप से प्रवर्चित किया जा रहा है, दिनांक 5 जनवरी, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2017- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क द्वारा आगे यथा संशोधित द्वारा लगाये गए थे।

घ. कथित परिवर्चना के आधार

5. परिवर्चना रोधी जाँच के लिए वर्तमान आवेदन दिनांक 5 जनवरी, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2017- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क द्वारा आगे यथा संशोधित द्वारा लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की पीयूआई परिवर्चना के संबंध में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने के लिए किया गया है। यह परिवर्चना "उत्पाद परिवर्चन" की श्रेणी में अधीन आती है। आवेदक ने परिवर्चना रोधी जाँच की मांग के लिए कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद संबद्ध देश से निर्यातों वाले व्यापार की प्रवृत्ति में भारी बदलाव हुए हैं। यह दावा किया गया है कि ऐसे बदलाव के लिए शुल्क लागू होने से इतर कोई आवश्यक कारण या औचित्य नहीं है।
- ख. साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि जाँच के अधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित मूल्यवर्धन पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(1)(ख) में यथा विहित 35 प्रतिशत की नियत सीमा से काफी कम है।

ग. साक्ष्य दर्शाते हैं कि व्यापार की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन जूट सैकिंग बैग्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद हुए हैं जिसके बाद न्यूनतम मूल्यवर्धन के साथ जूट सैकिंग बैग्स में परिवर्तन के लिए जूट सैकिंग क्लार्थ के आयातों में वृद्धि हुई है।

घ. इस अनुरोध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि जॉच के अधीन उत्पाद की कीमतें भी पाटित हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव जॉच के अधीन उत्पाद के आयातों में भारी मात्राओं के कारण निष्क्रिय हो रहा है जो विचाराधीन उत्पाद के आयातों को प्रतिस्थापित करता प्रतीत हो रहा है।

ड. प्रक्रिया

7. उपर्युक्त के आलोक में, यह निर्णय लिया गया है कि नियम 26 के अनुपालन में जॉच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 27 के अधीन प्राधिकारी यह निर्धारित होने पर कि पाटनरोधी शुल्क की परिवर्चना हो रही है मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की परिवर्चना पाये जाने पर पीयूआई के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाये जाने की सिफारिश कर सकते हैं और इसे नियम 26 के अधीन जॉच की शुरूआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।

च. जॉच की अवधि

8. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जॉच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 (12 महीने) की है। तथापि, अधिक हाल के और अद्यतन आकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने पीओआई में तीन महीने का विस्तार किया है और उसे 1 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2017 (15 महीने) के लिए माना है।

छ. शामिल देश

9. वर्तमान जॉच में शामिल देश बंगलादेश (संबद्ध देश) है।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

10. संबंधित ज्ञात निर्यातकों और आयातकों और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करने और जॉच में भाग लेने में सक्षम हो सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

झ. समय-सीमा

11. घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने पर, सभी हितबद्ध पक्षों जिनके पते उपलब्ध हैं को एक पत्र द्वारा सलाह दी जाएगी कि वे ऐसे पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में टिप्पणियां भेजे। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। सूचना हार्ड तथा साफ्ट कापियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ज. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

13. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पांच-पांच (5-5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

14. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

15. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

16. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

17. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

18. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

20. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March 2018

Subject: Initiation of Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of Jute Sacking Bags from Bangladesh.

No. 7/3/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or AD Rules).

WHEREAS, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in an antidumping investigation, vide its Final Findings Notification No 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016, had recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of “Jute Products” viz.-(Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags) originating in or exported from Bangladesh and Nepal, and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, as amended further by Notification No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3rd April, 2017.

AND WHEREAS, Indian Jute Mills Association (IJMA) on behalf of the domestic producers of Jute Sacking Bags (hereinafter referred to as the product under consideration (PUC)) has filed an application before the Authority in accordance with the Act and AD Rules alleging that the product under consideration (which is one of the product types of Jute products, the subject goods, on which original investigation was concluded) is being circumvented by imports of Jute Sacking Cloth (hereinafter referred to as Product Under Investigation (PUI)) which is an unfinished and penultimate form of the product under consideration only from Bangladesh (hereinafter referred to as Subject Country).

AND WHEREAS, the Authority having found sufficient prima facie evidence of circumvention of the anti-dumping duties leviable on the PUC by the subject country, hereby initiates an investigation into the alleged circumvention of the anti-dumping duties in terms of the Rules 26(1) of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged circumvention and to examine the need to extend the existing antidumping duty to the circumventing product.

A. Product under consideration

1. The product under consideration for this investigation is “Jute Sacking Bags” originating in or exported from Bangladesh. Jute Sacking Bags is classified under custom heading 6305. Jute Sacking Bag is one of the type of the product under consideration as identified in the final finding of the original investigation dated 20th October 2016.

B. Product under Investigation

2. The Product under Investigation is Jute Sacking Cloth, alleged to be circumventing the anti-dumping duty. The circumventing product goes into use of Jute Sacking Bags and there is no other main known use of the Product under Investigation.
3. The product under investigation is classified under custom heading 5310. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of this investigation.

C. Existing Measures

4. The existing anti-dumping measures imposed vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated 5th January, 2017 as amended further by Notification No. 11/2017-Customs (ADD) dated 03rd April 2017, are allegedly being circumvented.

D. Grounds for Alleged Circumvention:

5. The present application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duty levied on subject goods vide Custom Notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017 as amended further by Notification No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3rd April 2017 on PUI circumventing the existing anti-dumping duty. This circumvention comes under the category of “product circumvention”. The applicant has furnished reasons/ evidence for seeking anti-circumvention investigation which, inter alia, includes:

- a. Significant changes in the pattern of trade involving exports from subject country to post imposition of anti-dumping duties on the product under consideration. It has been claimed that there is no due cause or justification other than the imposition of the duty for such a change.
 - b. Evidence to prove that value addition required to convert product under investigation to product under consideration is well below the threshold limit of 35% as prescribed in the Rule 25 (1) (b) of AD Rules.
 - c. Evidence to indicate that this change in the pattern of trade coincides with the levy of anti-dumping duty on Jute Sacking Bags which thereafter lead to increase in imports of Jute Sacking Cloth for conversion to Jute Sacking Bags with minimal value addition.
 - d. The request contains sufficient prima facie evidence that the prices of the product under investigation are also dumped.
6. The remedial effects of the existing anti-dumping duties on the product under consideration are being undermined on account of the significant volumes of imports of the product under investigation which appears to indicate replacing the imports of the product under consideration.

E. Procedure

7. In light of the above, it is decided that sufficient evidence exists to justify the initiation of an investigation pursuant to Rule 26. It is also noted that in terms of Rule 27 of AD Rules, the Authority, upon determination that circumvention of anti-dumping duty exists, may recommend extension of anti-dumping duty to imports of PUI found to be circumventing an existing anti-dumping duty and such levy may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under Rule 26.

F. Period of Investigation:

8. The Period of investigation (POI), as proposed by the applicant, is from 1st October 2016 to 30th September 2017 (12 months). However, to make the required analysis on the basis of more recent and updated data, the Authority has extended the POI by three months and considered it as 1st October 2016 to 31st December 2017 (15 months).

G. Country Involved

9. The country involved in the present investigation is Bangladesh (subject country).

H. Submission of Information

10. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi- 110001

I. Time limit

11. On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

J. Submission of Information on Confidential basis

12. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-
- (a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - (b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
13. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-

confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

14. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
15. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
16. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
17. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
18. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

19. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

20. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Designated Authority